Regarding grant of special status to Bihar-laid

श्री कौशलेन्द्र कुमार **(नालंदा) :** नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को देश का सर्वाधिक गरीब राज्य बताया गया है । बिहार में प्रति व्यक्ति आय मानव विकास व जीवन स्तर के मानकों पर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है । बिहार में प्राकृतिक संसाधनों व जलीय सीमा के अभाव तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी इसका एक कारण है. साथ ही बिहार बाढ व सुखाड़ से प्रभावित प्रदेश भी है । केन्द्र सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी अभी तक कोई पहल नहीं की है, जबकि उत्तर के 3 राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश एव नार्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ औद्यागिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है ।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है । इससे बिहार आर्थिक सब्सिडी और टैक्स देने में सक्षम होगा । ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उत्तर के 3 राज्य और नार्थ-ईस्ट में केन्द्र की पहल का जो परिणाम आया है वही परिणाम बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्राप्त होगा ।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नार्थ ईस्ट राज्यों के तर्ज पर एवं 9 मार्च, 2024, गजट संख्या-पी-44015/1/2023-डीबीआर-2. नाथ-ईस्ट को औद्योगिकीकरण स्कीम 2024 के आधार पर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये ।